Incentive schemes for National Hydro Power Corporation Employees

1444. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the incentive schemes drawn by the National Hydro Power Corporation (NHPC) for the years 1983-84 to 1986-87 for the employees upto the scale of Rs. 425—800 were linked to Dearness Allowance pattern;

(b) if so, whether this policy has been followed by Government side also; and

(c) if not, what are the reasons for non-payment of the incentives to the NHPC employees in the scale of Rs. 550—900 and above?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) and (c) The National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) had formulated two Productivity Linked Incentive Schemes for its employees which, it was envisaged, would be valid initially for two years from 1.4.1985. It was also envisaged that a lump-sum award could be paid to the employees for 1983-84 and 1984-85. The scheme and the lumpsum payment were applicable to the employees of the Corporation who have accepted the Industrial DA pattern and, accordingly, these benefits were made available to the NHPC employees in the scales upto Rs. 425—800, who are on the Industrial DA pattern. The benefits of these schemes will also become available to the employees of NHPC in the scale of Rs. 550—900 and above when they accept the Industrial DA pattern.

(b) Does not arise since there is only one pattern of dearness allowance applicable to Central Government employees.

Mining operations by ECL in the areas owned by the West Bengal Government

1445. SHRI SUKOMAL SEN:
SHRI SUNIL BASU RAY:
SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Central Government have given permission to ECL to carry out its mining operations without taking permission from respective State Governments;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, how the ECL is carrying out its mining operations in the areas owned by the West Bengal Government and against which the State Government of West Bengal has raised objections?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) to (c) While Eastern Coalfields Limited has been carrying on mining operations only on lands for which it holds mining leases, a dispute has arisen between the Company and the West Bengal Government over mining operations in Mangalpur Mauja. This matter is *sub-judice*.

गुजरात में लिग्नाइट का उत्पादन

1446. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के लिग्नाइट के संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए कोई कार्यकारी दल गठित किया था। और

(ख) क्या कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्च, 1988 में गुजरात में लिग्नाइट की उपलब्धता और बनली उत्पादन तथा अन्य उद्देश्यों के लिए इनकी उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए एक "टास्क फोर्स" की स्थापना की गयी थी। इस "टास्क फोर्स" ने फरवरी, 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किए जाने के संबंध में योजना आयोग द्वारा कोयला तथा लिग्नाइट पर कार्यकारी दल के अंतर्गत लिग्नाइट तथा इससे सम्बद्ध पहलुओं पर नियुक्त किए गए उप दल ने गुजरात में लिग्नाइट के अन्वेषण तथा दोहन के प्रश्न के संबंध में भी विचार किया। गुजरात लिग्नाइट पर "टास्क फोर्स" की सिफारिशों को लिग्नाइट तथा उससे संबद्ध पहलुओं पर उप दल की रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है।

इन मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) राज्य के लिग्नाइट धारी क्षेत्रों में अन्वेषण की भौमिकी तथा भूभौतिकी पद्धति का प्रयोग करते हुए एक-3 चरणीय कार्यक्रम।

(2) भारतीय भू सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए जाने वाला एक दीर्घ-अवधि क्षेत्रीय अन्वेषण कार्यक्रम।

(3) उपयुक्त प्राथमिकताओं के साथ एकरिमोटा, उमरसर, लखपत, भननमोघ और भावनगर के लिग्नाइट क्षेत्रों में एक विस्तृत कार्यक्रम को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) एक व्यवसायिक दल द्वारा गुजरात में लिग्नाइट का विकास करने के लिए एक मास्टर प्लान को शीघ्रतम तैयार करना।

(5) स्वयं-अन्वेषण स्तर पर उपयुक्त पर्यावरणीय अध्ययन की शुरुआत करना ताकि खनन स्कीमों का निष्पादन और एकको की उपयोगिता की "डाउन-स्ट्रीम" में लगी अधिक समयावधि से बचा जा सके।

(6) गुजरात लिग्नाइट के संबंध में एक ठोस उपयोगिता नीति का निष्पादन जिसमें लघु डिटेच अवतरित भागों में इसकी प्राप्ति उच्च सल्फर की प्राप्ति और लिग्नाइट धारी क्षेत्रों में जल की नगण्य उपलब्धता को ध्यान में रखा जायेगा।

(7) उन "स्माल कलस्टर्स" भण्डारों का विकास जिनका गैर-विद्युतीय उप-भोक्ताओं के साथ संयोजन किया जाना है।

(8) गुजरात में लिग्नाइट भण्डारों के अन्वेषण, दोहन तथा उपयोगिता से संबंधित कार्यों के विभिन्न पहलुओं को योजनागत करने के लिए एक अन्तर-विषयीय स्थायी विशेषज्ञ दल का गठन।

(9) केन्द्रीय तथा राज्यों को एजेंसियों के एक नीति दल का गठन करना जो कि समय-समय पर लिग्नाइट के अनवेषण, दोहन तथा उपयोगिता के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करेगें।

लिग्नाइट और उससे सम्बद्ध पहलुओं पर उप दल ने वर्ष 2005 तक ड्रिलिंग द्वारा 3.20 ल.ख मीटर तक विस्तृत लिग्नाइट अन्वेषण किए जाने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम भी तैयार किया है।

Foreign bank loans for private parties for setting up power plants

1447. **SHRI SURESH PACHOURI :** Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to make private sector accessible to foreign banks for loans for the setting up of power plants in the country;

(b) how many private sector parties have so far offered to set up power plants in the country;

(c) what are the names of the foreign banks which have agreed to help these private sector parties; and

(d) whether any conditions are being imposed on such loans ?